

विकसित भारत @ 2047 और वित्तीय समावेशन एवं वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता डॉ० ब्रजेश श्रीवास्तव¹

¹सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही उ०प्र०

Received: 25 November 2025 Accepted & Reviewed: 28 November 2025, Published: 30 November 2025

Abstract

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 2047 तक विकसित भारत के लिए भारत का लक्ष्य देश को वर्तमान 3.8 ट्रिलियन डॉलर से 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें वित्तीय समावेशन प्रत्येक नागरिक को लाभान्वित करने वाले आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। परिवहन, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र और शहरी विकास में बुनियादी ढाँचे की प्रगति ने गति पकड़ी है, फिर भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करना एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।

मुख्य शब्द – विकसित भारत, वित्तीय समावेशन, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय क्षमता

Introduction

आर्थिक खाई को पाटने और समग्र आर्थिक लचीलापन बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन आवश्यक है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, 65–70% संपत्तियाँ वित्तीय होती हैं, जैसे बचत, निवेश और इक्विटी। हालाँकि, भारत में, 75% संपत्ति गैर-वित्तीय संपत्तियों जैसे रियल एस्टेट, सोना और टिकाऊ वस्तुओं से जुड़ी है, जिससे तरलता और वित्तीय गतिशीलता सीमित हो जाती है। संपत्तियों के अधिक वित्तीयकरण को प्रोत्साहित करने से न केवल आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सतत आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

वित्तीय समावेशन में भारत की प्रगति— वर्ष 2014 से पहले, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के केवल 44% भारतीयों के पास बैंक खाता था, जिसके कारण कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में अक्षमताएँ और अनियमितताएँ थीं। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) ने वित्तीय सुगमता में क्रांति ला दी है और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं :

- पिछले नौ वर्षों में 50 करोड़ से ज्यादा नए बैंक खाते खोले गए हैं।
- 15 वर्ष से अधिक आयु के 78% भारतीयों के पास अब बैंक खाते हैं।
- पीएमजेडीवाई के माध्यम से ₹2 लाख करोड़ से अधिक जमा राशि जुटाई गई है।

आरबीआई के आंकड़ों (2024) के अनुसार, वित्तीय समावेशन सूचकांक 64.2 पर है, जो एक वर्ष के भीतर 300 आधार अंकों का सुधार दर्शाता है। जेएएम त्रिमूर्ति (जन धन, आधार, मोबाइल) की सफलता ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) में उल्लेखनीय सुधार किया है, अक्षमताओं को कम किया है और यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय लाभ इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचें, जिससे विकसित भारत @ 2047 की रूपरेखा को और बल मिला है।

आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका— ऋण तक पहुँच वित्तीय सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, विशेष रूप से निम्न-आय वर्ग के लिए। सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के उदय ने ऋण तक पहुँच को बढ़ाया है और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए हैं। सूक्ष्म वित्त की 30% पहुँच के साथ, वित्तीय पहुँच में सुधार हुआ है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं :

- जिम्मेदार ऋण चूक (default) में तेज वृद्धि उधारकर्ता की मंशा और वित्तीय अनुशासन के अधिक कठोर मूल्यांकन की आवश्यकता को इंगित करती है।
- उत्पादक ऋण उपयोगरू ऋण मुख्य रूप से सोशल मीडिया से प्रभावित आकांक्षात्मक खर्च के बजाय आय-उत्पादक गतिविधियों पर केंद्रित होने चाहिए।

पूर्ण वित्तीय समावेशन प्राप्त करने में चुनौतियाँ— उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, कई बाधाएँ बनी हुई हैं :

- कम वित्तीय साक्षरता— कई नागरिक बैंकिंग, निवेश और वित्तीय प्रबंधन के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
- डिजिटल अवसंरचना की कमी— ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुँच और वित्तीय सेवाओं की पहुँच प्रगति में बाधा डालती है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएँ— डिजिटल बैंकिंग पर बढ़ती निर्भरता ने धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटालों से संबंधित जोखिम बढ़ा दिए हैं।
- अति-ऋणग्रस्तता—ऋण की आसान उपलब्धता, विशेष रूप से सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों (MFI) से, कमजोर समूहों में अस्थिर उधारी प्रथाओं को जन्म दे रही है।

वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की रणनीतियाँ— वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए, निम्नलिखित रणनीतिक कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए—

- वित्तीय साक्षरता पहलों का विस्तार— राष्ट्रव्यापी शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और जिम्मेदारी से उधार लेने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
- नियामक निगरानी को बढ़ाना—ऋण देने वाली संस्थाओं की कड़ी निगरानी से शिकारी ऋण और अति-ऋणग्रस्तता को रोकने में मदद मिलेगी।
- फिनटेक नवाचार को प्रोत्साहित करना— निजी क्षेत्र का सहयोग और फिनटेक समाधान बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकते हैं।
- जिम्मेदार ऋण उपयोग को बढ़ावा देना—वित्तीय संस्थानों को विवेकाधीन खर्च के बजाय उत्पादक निवेश के लिए ऋणों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ऐसी दुनिया में जहाँ वित्तीय परिदृश्य लगातार बदल रहे हैं, व्यक्तिगत वित्त को नियंत्रित करना सफलता के लिए एक आवश्यक कौशल बन गया है। जैसा कि रॉबर्ट कियोसाकी ने ठीक ही कहा था, 'वित्तीय स्वतंत्रता उन्हीं को मिलती है जो इसके बारे में सीखते हैं और इसके लिए काम करते हैं।' वित्तीय साक्षरता सिर्फ एक प्रचलित शब्द नहीं हैय यह वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते

हैं। एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहाँ हर व्यक्ति के पास सही वित्तीय निर्णय लेने का ज्ञान और आत्मविश्वास हो—यह सशक्तिकरण एक विकसित भारत (विकसित भारत) के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्कूली प्रारंभिक शिक्षा में, अपने वित्त का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में ज्यादा नहीं सीखते, इसलिए भविष्य में, समस्याएं आती हैं। अगर हम (बच्चे) अभी से वित्तीय प्रबंधन की समझ पर काम शुरू करते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। तो वित्तीय साक्षरता क्या है? इसमें बजट बनाना, बचत करना, निवेश करना और ऋण प्रबंधन जैसे जरूरी कौशल शामिल हैं। विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से हम धन और विभिन्न संपत्तियों का प्रबंधन करना सीख सकते हैं। इसके लिए विभिन्न वित्तीय उत्पादों और व्यक्तियों व उनके परिवारों पर वित्तीय विकल्पों के दीर्घकालिक प्रभाव की स्पष्ट समझ आवश्यक है।

वित्तीय रूप से शिक्षित होना निम्नलिखित कारणों से जरूरी है –

- वित्तीय रूप से साक्षर व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति कम संवेदनशील होते हैं।
- वित्तीय ज्ञान का एक ठोस आधार महत्वपूर्ण जीवन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, जिसमें शिक्षा, सेवानिवृत्ति या व्यवसाय शुरू करने के लिए बचत करना शामिल है।
- वित्तीय साक्षरता महंगी वित्तीय गलतियों को रोकने में महत्वपूर्ण है।
- यह व्यक्तियों को वित्तीय आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करती है।
- यह लोगों को अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुँचने और उन्हें पार करने में सक्षम बनाती है।

वित्तीय साक्षरता आर्थिक विकास का एक शक्तिशाली इंजन है। वित्तीय ज्ञान से लैस व्यक्ति बचत और निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिससे पूँजी निर्माण होता है जो आर्थिक विकास को गति देता है। इसके अलावा, ये व्यक्ति व्यवसाय स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं, जिससे रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिलता है।

वस्तुतः वित्तीय साक्षरता हमारे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी है, इसलिए यह हमारे समग्र स्वास्थ्य से भी जुड़ा है। इसलिए हमें वित्तीय साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि वित्तीय तनाव मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वित्तीय साक्षरता वाले व्यक्ति वित्तीय चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं और उन्हें पैसों से जुड़े तनाव का सामना करने की संभावना कम होती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है और समाज अधिक खुशहाल बनता है।

यह सरकार के लिए भी मददगार है क्योंकि एक वित्तीय साक्षरता वाला व्यक्ति एक अधिक जिम्मेदार नागरिक होता है क्योंकि वित्तीय साक्षरता वाले नागरिक कराधान, सरकारी खर्च और आर्थिक मुद्दों से संबंधित सार्वजनिक नीतियों के निहितार्थों को समझने में अधिक सक्षम होते हैं। इससे एक अधिक जागरूक और सक्रिय नागरिक वर्ग बनता है, जो शासन और सार्वजनिक मामलों में बेहतर निर्णय लेने में योगदान देता है।

एक वित्तीय रूप से जागरूक आबादी बचत के महत्वपूर्ण महत्व और निवेश के लाभों को समझती है। यह समझ न केवल उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करती है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थिर निधि भी उत्पन्न करती है। बढ़ी हुई बचत बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में

अधिक निवेश में परिवर्तित होती है, जो सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। मैंने यह भी सीखा है कि निवेश करना न केवल अच्छा है, बल्कि महान भी है। हाल के वर्षों में, मैंने अपने जन्मदिन पर मिले पैसों से सोने में निवेश किया।

वित्तीय साक्षरता उद्यमशीलता की संभावनाओं को उजागर करने की कुंजी है। यह व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक ज्ञान और आत्मविश्वास से लैस करती है। उद्यमी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं वे रोजगार सृजित करते हैं, नवाचार को बढ़ावा देते हैं और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देकर, वित्तीय साक्षरता बेरोजगारी को नाटकीय रूप से कम कर सकती है और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दे सकती है।

वित्तीय साक्षरता गरीबी को काफी हद तक कम कर सकती है और असमानता को कम कर सकती है। जब व्यक्ति अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सीख जाते हैं, तो समय के साथ उनके धन संचय करने की संभावना बढ़ जाती है। इससे संसाधनों और अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सकता है।

स्पष्ट लाभों के बावजूद, भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में कई चुनौतियाँ हैं। इनमें जागरूकता की कमी, वित्तीय शिक्षा तक सीमित पहुँच और सांस्कृतिक बाधाएँ शामिल हैं। कई लोग, खासकर ग्रामीण इलाकों में, वित्तीय साक्षरता के महत्व से अनजान हैं। वित्तीय शिक्षा तक पहुँच अक्सर सीमित होती है, खासकर दूरदराज और वंचित इलाकों में। वित्तीय शिक्षा के लाभों पर प्रकाश डालने वाले लक्षित जागरूकता अभियानों के माध्यम से इसका समाधान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक सेवा घोषणाएँ और सामुदायिक कार्यशालाएँ जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

धन और वित्तीय प्रबंधन के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी एक चुनौती बन सकते हैं। कुछ समुदायों में, धन पर चर्चा करना वर्जित माना जाता है, और पारंपरिक प्रथाएं आधुनिक प्रथाओं को अपनाने में बाधा बन सकती हैं। वित्तीय व्यवहार इन बाधाओं को दूर करने के लिए सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील दृष्टिकोणों की आवश्यकता है जो स्थानीय मूल्यों और परंपराओं का सम्मान और समावेश करें, जैसे कि वित्तीय शिक्षा प्रयासों में सामुदायिक नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को शामिल करना।

अतः वित्तीय रूप से साक्षर आबादी का निर्माण करने और विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में वित्तीय शिक्षा को शामिल करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और विभिन्न हितधारकों को शामिल करना शामिल है। स्कूली पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में वित्तीय साक्षरता को शामिल करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि बच्चे कम उम्र से ही वित्तीय कौशल विकसित करें। इसमें बजट बनाने, बचत करने और निवेश करने के साथ-साथ वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को समझने के व्यावहारिक पाठ शामिल हो सकते हैं। स्कूल छात्रों को वास्तविक दुनिया की अंतर्दृष्टि और अनुभव प्रदान करने के लिए वित्तीय विशेषज्ञों के साथ साझेदारी कर सकते हैं। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मोबाइल ऐप, ऑनलाइन पाठ्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म देश भर के व्यक्तियों को सुलभ और इंटरैक्टिव वित्तीय शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष— भारत ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से पीएमजेडीवाई और जेएएम ट्रिनिटी के माध्यम से, जिसने बैंकिंग पहुँच में क्रांति ला दी है। हालाँकि, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विस्तार करने और जिम्मेदार ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। वित्तीय साक्षरता एक विकसित भारत की आधारशिला है। व्यक्तियों को अपने वित्त का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाकर, हम आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। हमें वित्तीय शिक्षा में निवेश करना चाहिए और एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ प्रत्येक नागरिक को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने और राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करने का अवसर मिले। इन चुनौतियों का समाधान करके, भारत वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता को गति दे सकता है ताकि विकसित भारत @ 2047 के विजन को साकार करने के करीब पहुँच सके। आगे का रास्ता एक वास्तविक समावेशी और लचीली अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों और निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण की माँग करता है।

सन्दर्भ सूची

- [1] Prasad, R (2020) - "Financial Literacy in India: Current State and Future Directions", Journal of Economic Perspectives, vol-34, no- 2 pp- 235-250.
- [2] Sharma, A (2020) - "The Role of Financial Literacy in Enhancing the Growth of Indian SMEs" Asian Journal of Business Management, vol- 12, no- 3, pp- 112-118
- [3] Kumar, S (2020) - "Financial Literacy and the Importance of Investment in India", International Journal of Financial Research, vol- 11, no- 4, pp- 45-58.